यह एक मजदूरी संकट है

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

लेखक-मनीष सभरवाल (अध्यक्ष, टीमलीज सर्विसेज)

15 फरवरी, 2019

"भारत की चुनौती उच्च उत्पादकता वाली फर्मों का एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।"

बेरोजगारी के मुद्दे के इर्द-गिर्द हो रही बहस व्यर्थ है क्योंकि 1947 के बाद से, बेरोजगारी भारत की श्रम शक्ति के 3-7 प्रतिशत के बीच रही है, लेकिन हमारी दरिद्रता, जो 1947 के बाद से हमारी आबादी के 25-75 प्रतिशत के बीच रही है और यह हमारी जरूरतों, इच्छाओं और आवश्यकताओं की परिभाषा के आधार पर आधारित है, के साथ इस गणितीय सटीकता का सामंजस्य स्थापित करने के लिए हमें 1920 के दशक में रूसी अर्थशास्त्री अलेक्जेंडर च्यानोव द्वारा प्रस्तावित 'आत्म-शोषण' के सिद्धांत को समझने की आवश्यकता है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को यकीन दिलाया कि छोटे कृषि क्षेत्र उपयुक्त होते हैं क्योंकि इसमें आपको अपने आप को किराए का भुगतान या अपने जीवनसाथी या बच्चों को वेतन नहीं देना पड़ता है। मेरे अनुसार (लेखक) आत्म-शोषण, जिसका अर्थ खेतों में कम या शून्य सीमांत उत्पादकता, स्व-रोजगार या निर्वाह मजदूरी रोजगार के साथ निकम्मा (बेकार) बैठना है, 1947 से भारतीय श्रम बाजार का शॉक ऑब्जर्वर रहा है। दूसरा, यह शॉक ऑब्जर्वर अब भारत में काम नहीं करता है क्योंकि 1991 के बाद पैदा हुए भारतीय न्यूनतम मजदूरी (जो मन और शरीर को एक साथ रखते हैं) के बजाय एक बेहतर मजदूरी (जो आकांक्षाओं को पूरा करते हैं) की अपेक्षा करते हैं और तीसरा, ये उच्च मजदूरी अपेक्षाएं केवल लोगों को उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों, भौगोलिक और फर्मों में परिवर्तित करके पूरी की जा सकती हैं।

हमारी वर्तमान बहस रोजगार को मजदूरी समझने की गलती करती है। लगभग हर भारतीय जो नौकरी चाहता है, उसके पास नौकरी तो है, लेकिन उन्हें वह मजदूरी नहीं मिलती, जो वे चाहते हैं क्योंकि वे अव्यवहार्य क्षेत्रों में काम करते हैं (खेतों पर हमारे श्रम बल का 48 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद का केवल 13 प्रतिशत ही उत्पन्न करता है) अव्यवहार्य फर्में (हमारे 6.3 करोड़ उद्यम केवल 19,500 कंपनियों को 10 करोड़ रुपये से अधिक की चुकता पूंजी को परिवर्तित करते हैं),अव्यवहार्य उद्यमिता (हमारी श्रम शक्ति का 50 प्रतिशत स्वरोजगार नहीं, बल्कि आत्म-शोषण है)और अव्यवहार्य भौगोलिक (हमारे 6 लाख गांवों में से 2 लाख गांवों में 200 से कम लोग हैं)।

इतिहासकार रामचंद्र गुहा हमें याद दिलाते हैं कि भारत भले ही दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली देश न हो, लेकिन यह निश्चित रूप से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहा है। हमारे राजनीतिक दलों ने दुनिया के सबसे पदानुक्रमित समाज की बंजर मिट्टी पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया है। लेकिन हमारे पास 1955 के अवाडी संकल्प और 1956 की दूसरी पंचवर्षीय योजना द्वारा व्यक्त आर्थिक मॉडल की बंजर मिट्टी पर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की शून्य संभावना थी।

उच्च मजदूरी को उच्च उत्पादकता फर्मों और व्यक्तियों के एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता है: आईटी फर्म भारत की श्रम शक्ति का केवल 0.7 प्रतिशत हिस्सा है, लेकिन भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 7 प्रतिशत उत्पादन करती हैं। जयपुर में वेटर के समान कौशल वाला शिकागो में एक वेटर रेस्टोरेंट में खाने वाले ग्राहकों की उत्पादकता के कारण 20 गुना अधिक मजदूरी पाता है और भारत के 20 मिलियन मैन्युफैक्चरिंग एसएमई की जर्मनी की 200,000 मित्तल स्टैंड (एसएमई) की तुलना में कम से कम 25 गुना कम उत्पादकता है।

अनिवार्य रूप से, 114 मिलियन महाराष्ट्रियों की जीडीपी उत्तर प्रदेश में 204 मिलियन लोगों से अधिक है क्योंकि महाराष्ट्र अधिक औपचा. रिक, औद्योगिक, वित्तीय, शहरीकृत और कुशल राज्य है। इसी तरह, 2019 तक 1.2 बिलियन भारतीयों की जीडीपी 66 मिलियन ब्रिटिशों से कम थी क्योंकि समाजवाद, प्रतिस्पर्धा और दिवालियापन के बिना पूंजीवाद, ने 1947 के बाद बेहतर अर्थशास्त्र का नेतृत्व किया था। तीन पुस्तकें - कैपिटलिज्म इन अमेरिका; ए हिस्ट्री बाई एलन ग्रीन स्पैन और एड्रियन वोल्ड्रिज; हाउ चाइना एस्केप्ड द पॉवर्टी ट्रैप बाई यूएन एंग, और लॉस्ट इंडियाज कैपिटलिज्म स्टोरी बाई सुमित मजूमदार - विकल्पों और परिणामों के बारे में बात करती है।

अमेरिका में समृद्धि बढ़ी (आधिकारिक गरीबी में 35 फीसदी लोगों के पास एयर कंडीशनिंग और 60 फीसदी के पास कार है), चीन ने 1978 के बाद से 700 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए बाजारों का उपयोग किया है, जबकि हमारे लाइसेंस-राज ने अक्षमता को जन्म दिया है। राजनीतिज्ञ वसंत साठे ने 1980 के दशक में बताया कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उद्योग ने दक्षिण कोरियाई लोगों के आधे स्टील का उत्पादन करने के लिए 10 गुना अधिक लोगों को रोजगार दिया।

लेकिन भारत अब अपने अतीत को पीछे छोड़ने की तैयारी में जुट गया है। जीएसटी के बाद हमारे पास छह मिलियन नए पंजीकृत उद्यम हैं और तीन वर्षों में 30 मिलियन नए सामाजिक सुरक्षा भुगतानकर्त्ता हैं। हमारी नई मौद्रिक नीति समिति और राजकोषीय अनुशासन ने 2014 में मुद्रास्फीति को 8.33 प्रतिशत से घटाकर 2.19 प्रतिशत कर दिया है। हमारे नए दिवालियापन कानून ने 14 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति की रिसाइक्लिंग शुरू कर दी है।

1960 के दशक में, तत्कालीन आरबीआई गवर्नर एल.के.झा ने चेतावनी दी थी कि संसाधन का उपयोग, संसाधन जुटाना जितना महत्वपूर्ण है। विमुद्रीकरण से पहले जो डिजिटल भुगतान 0.1 मिलियन था, वह पिछले महीने बढ़कर 650 मिलियन हो गया है। पिछले पांच वर्षों में एयर कनेक्टिविटी, बंदरगाहों, राजमार्गों और रेलवे में गुणात्मक सुधार के साथ बुनियादी ढांचे का खर्च दोगुना हो गया है। अंत में, एक आधुनिक देश एक व्यापक कर

आधार वाला एक कल्याणकारी देश है; पिछले साल 10 लाख रुपये से कम आय वाले रिटर्न में 45 प्रतिशत वृद्धि के साथ विमुद्रीकरण के बाद से भारत में एक करोड़ से अधिक व्यक्तिगत टैक्स फाइल करने वाले हैं।

1972 में भारत के 25वें जन्मदिन पर, स्वर्गीय शीला धर ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि भारतीयों में बहुत धैर्य है। जल्दबाजी में रहना उनके स्वभाव में नहीं है। वे लंबे समय तक इंतजार कर सकते हैं, अन्य लोगों की तुलना में अधिक पीड़ा सह सकते हैं और कड़ी मेहनत कर सकते हैं। हालांकि, स्वर्गीय शीला धर द्वारा कही गयी ये बातें 2022 में भारत के 75वें जन्मदिन पर शायद बदल जाएंगी क्योंकि अब हमारे युवाओं की अधीरता भारत और उसकी राजनीति को बदल रही है और शुक्र है कि हमारे लोकतंत्र का अर्थ 1980 के दशक में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की रणनीति (लोगों का पेट भरें लेकिन उनका दिमाग खाली रखें) भारत में काम नहीं करेगी।

देखा जाये, तो आत्म-शोषण की हमारी स्वीकृति मानसिक बंधन का एक रूप थी, जिसने हमारे देश के रवींद्रनाथ टैगोर के सपने की उपेक्षा की। जिनका सपना था कि भारत एक ऐसा देश बने, जहाँ हर एक व्यक्ति का मन भय के बिना हो और उसका सिर हमेशा ऊंचा रहे। 1910 में, टैगोर ने इस दृष्टि को 'चित्तो जेथा भूयशूनो'में व्यक्त किया था। उम्मीद करते हैं कि उनका देश एक ऐसी स्वतंत्रता के लिए जागृत होगा। भारत की चुनौती रोजगार नहीं है, बल्कि गरीबी है और इस संदर्भ में बहुत अधूरा काम बचा हुआ है।

GS World टीम...

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में देश में रोजगार से जुड़ी नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस (एनएसएसओ) की एक रिपोर्ट लीक हुई।
- रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2017-18 में बेरोजगारी दर 45 साल में सबसे ज्यादा 6.1% के स्तर पर पहुंच गई है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 की बेरोजगारी दर 1972-73 के बाद सबसे ज्यादा है।
- देश के शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर 7.8 फीसदी जबकि ग्रामीण इलाकों में 5.3 फीसदी है।
- 15-29 साल के शहरी पुरुषों के बीच बेरोजगारी की दर 18.7 फीसदी है। 2011-12 ये दर 8.1 फीसदी थी।
- 2017-18 में शहरी महिलाओं में 27.2 फीसदी बेरोजगारी है जो 2011-12 में 13.1 फीसदी थी।
- एनएसएसओ सर्वे के अनुसार वर्ष 2011-12 में यह देश में यह बेरोजगारी दर 2.2 प्रतिशत थी।

शहरी क्षेत्रों में

- पिछले सालों की तुलना में अभी देश में बेरोजगार युवाओं की संख्या काफी अधिक है और यह कुल जनसंख्या के मुकाबले बहुत अधिक है।
- शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर ग्रामीण क्षेत्रों से भी ज्यादा रही। यहाँ बेरोजगारी दर पुरुषों में 18.7 प्रतिशत और महिलाओं में 27.2 प्रतिशत रही।
- पीएलएफएस एनएसएसओ का पहला सालाना हाउसहोल्ड सर्वे है, जिसके लिए जुलाई, 2017 से जून, 2018 के दौरान आंकड़े जुटाए गए थे।
- 2017-18 में महिलाओं के लिए श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) में गिरावट देखी गई और यह 23.3 फीसदी रही, जबकि वित्त वर्ष 2011-12 में यह 31.2 फीसदी और 2009-10 में 32.6 फीसदी रही।
- पुरुषों के लिए एलएफपीआर 2011-12 में 79.8 फीसदी था, जो 2017-18 में 75.8 फीसदी रह गया। इसका मतलब है कि पुरुषों की तुलना में ज्यादा महिलाएं श्रम नौकरियों से बाहर हो रही हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में

- ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की बेरोजगारी दर 2017-18 में 13.6 प्रतिशत रही, जो 2011-12 में 4.8 प्रतिशत थी।
- शिक्षित ग्रामीण महिलाओं में 2004-05 से 2011-12 तक बेरोजगारी दर 9.7 प्रतिशत से 15.2 प्रतिशत के बीच रही है। 2017-18 में यह बढ़कर 17.3 प्रतिशत हो गई।
- शिक्षित ग्रामीण पुरुषों के लिए बेरोजगारी दर बढ़कर 10.5 प्रतिशत हो गई, जो 2004-05 से 2011-12 के दौरान 3.5-4.4 प्रतिशत के बीच रही।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 15-29 आयु वर्ग के युवाओं में 2011-12 के दौरान बेरोजगारी दर 5 प्रतिशत थी, जो 2017-18 में तीन गुना से ज्यादा बढ़कर 17.4 प्रतिशत हो गई।

क्या है?

- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय को ही राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के नाम से भी जाना जाता है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी।
- यह भारत का सबसे बड़ा संगठन है, जो नियमित रूप से देश का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करता है।
- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

क्या कहा नीति आयोग ने?

- ऐसा कोई भी डेटा सरकार की तरफ से रिलीज नहीं किया गया है।
- सरकार तिमाही डेटा पेश करेगी।
- एनएसएसओ का डेटा पूरी तरह से गलत है।
- नीति आयोग के मुताबिक 7-7.8 मिलियन नौकरियां दी गई हैं।
- देश को अभी 7 मिलियन नौकरियों की जरूरत है।
- मार्च तक नीति आयोग रिपोर्ट जारी करेगा।
- रोजगार को लेकर अभी आंकड़े तैयार हो रहे हैं।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

   1. भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का केवल 13% भाग है।
   2. आई.टी. क्षेत्र में भारत की श्रम शक्ति का केवल 0.7 प्रतिशत हिस्सा है, लेकिन यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 7 प्रतिशत उत्पादन करता है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 और न ही 2

1. **Consider the following statements-**

   1. Agriculture sector contributes only 13 percent part of Gross Domestic product in India.
   2. IT sector in India only employs 0.7 percent but it produces 7 percent of gross domestic product of India.

   Which of the above statements is/are correct?

   (a) Only 1
   (b) Only 2
   (c) Both 1 and 2
   (d) Neither 1 nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्नः क्या आप मानते हैं कि भारत की चुनौती रोजगार नहीं, बल्कि गरीबी है? चर्चा कीजिए।
Q. Do you agree that the challenge before India is not employment but poverty? Discuss.

(250 Words)

नोट : 14 फरवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b) होगा।

GS World
Committed To Excellence